साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 15-21 नवंबर 2021, वर्ष-7, अंक-33

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मंडियों का मास्टर प्लान तैयार करवा रही शिवराज सरकार

संवाददाता, भोपाल।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियों की बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए शिवराज सरकार अब मंडियों का मास्टर प्लान तैयार करवा रही है। इसमें अनुपयोगी भूमि का उपयोग कृषि से जड़े उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाएगा। किसान जब उपज लेकर मंडी पहुंचेगा तो उसे ग्रेडिंग कराने के लिए सारटेक्स मशीन उपलब्ध होगी।

इसी तरह मिनी प्रसंस्करण इकाई व पैकिंग सुविधा भी मिलेगी। इससे किसान को उपज की उचित कीमत मिल सकेगी। कृषि से जुड़े उद्योग लगाने के लिए निजी क्षेत्र को मंडियां कलेक्टर दर के हिसाब से भूमि उपलब्ध कराएंगी। इससे मंडियों की अनुपयोगी भूमि का उपयोग भी हो जाएगा और किसान को एक जगह पर उपज को गुणवत्तायुक्त बनाने की सुविधा भी मिल जाएगी।

प्रदेश की मंडियों में अभी उपज की नीलामी के लिए खरीद-बिक्री के लिए प्लेटफार्म, दुकानें और गोदाम उपलब्ध हैं। जबकि, मंडियों के पास काफी भूमि है, जो खाली पड़ी हुई है। इसका सदुपयोग किसानों की आय बढ़ाने के लिए करने की कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत सभी मंडियों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें भूमि का उपयोग सिर्फ कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाएगा।

उद्योगों की स्थापना पर होगा जोर

निजी सहभागिता से ऐसे उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। इसके लिए सारटेक्स मशीनें लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे किसान जब उपज लेकर मंडी आएगा तो वो ग्रेडिंग करा सकेगा। इससे उसे उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। वहीं, छोटी दाल मिल और गोदाम की स्थापना भी की जाएगी। इससे किसान यदि कुछ फसल बाद में बेचने के लिए रखना चाहता है तो उसे उपज को कहीं और नहीं ले जाना होगा। बायोफ्यूल तैयार करने के लिए संयंत्र लगाने के लिए भी मंडी की भूमि दी जाएगी।

प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की भविष्यवाणी, कहा

कृषि को बनाएंगे लाभ का धंधा पांच साल में खत्म होगी गरीबी

संवाददाता, भोपाल।

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गरीबी और बेरोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले पांच साल में प्रदेश व देश से बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो जाएगी। हम जैविक खेती का मॉडल अपना कर कृषि को लाभ का धंधा बना देंगे। किसान खुद अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर एमआरपी तय करेंगे।

पटेल ने कहा कि पीएम ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा कर गांव और शहरों की खाई को मिटाने का प्रयास किया है। अभी गांवों में बनने वाले मकान व प्लॉट की कोई कीमत नहीं होती थी। बैंक उस पर ऋण नहीं देती थी। उसका मालिकाना हक और वैल्यू नहीं था।

छग का गोधन मॉडल एमपी में भी करेंगे लागू

कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन योजना को हम एमपी में भी अपनाएंगे। अच्छे कार्यों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने पंजाब-हरियाणा में पेस्टीफाइ से होने वाली पैदवार के चलते बीपी, कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब जमीन को जहरीला बनाने की बजाए जैविक खाद का उपयोग कर उसे स्वस्थ्य बनाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से बदल जाएगी तस्वीर

भारत फिर से बन जाएगा सोने की चिड़िया

कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक खाद-बीज के लिए ही ऋण मिलता था। अब उन्हें व्यवसाय के लिए भी कर्ज मिलेगा। चार-पांच साल के अंदर बेरोजगारी और गरीबी नाम की चीज नहीं होगी। अभी परिवार में एक कमाता है और सब खाते हैं। अब सभी को काम मिलेगा। सभी कमाएंगे तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा।

आदिवासी जिलों की जमीनों का जैविक प्रमाणीकरण कराएंगे

कृषि मंत्री ने कहा कि आदिवासी जिले डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा और झाबुआ जैसे जिलों की मिट्टी अभी पेस्टीफाई से जहरीली नहीं हुई है। यहां की जमीनों का जैविक प्रमाणीकरण कराएंगे। इसके बाद यहां के उत्पाद की ब्रांडिंग कर एक्सपोर्ट करेंगे। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी।

ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन

किसान महंगी यूरिया की बजाए नैनो तरल यूरिया का छिड़काव कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसकी लागत भी कम आएगी। विगत दिनों प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने चरगंवा रोड स्थित ग्राम ललपुर में फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव के प्रदर्शन का आयोजन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) द्वारा दलाल कृषि फार्म में किया गया था। कृषि मंत्री के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल भी मौजूद थे। इफ्को के अधिकारियों ने बताया की नैनो तरल यूरिया, यूरिया का बेहतर विकल्प है। यूरिया की तुलना में नैनो तरल यूरिया का उपयोग कहीं ज्यादा आसान है और यह यूरिया से सस्ता होता है। फसल पर इसका छिड़काव पानी में मिलाकर किया जाता है।

कृषि विवि के बायोफर्टिलाइजर सेंटर का अवलोकन

इसके पहले कृषि विकास मंत्री पटेल ने सुबह हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल के साथ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बायोफर्टिलाइजर सेंटर का अवलोकन किया। यहां मौजूद कृषि वैज्ञानिकों चर्चा की और उन्हें जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के लिये किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

चित्रकारी के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार हैं भूरी बाई

आदिवासी चित्रकार भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान, बढ़ा प्रदेश का मान

संवाददाता। भोपाल

मध्यप्रदेश की भूरी बाई को इस बार पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। मध्यप्रदेश में झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरी बाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार, शिखर सम्मान द्वारा कलाकारों को दिए गए सर्वोच्च राजकीय सम्मान सहित कई पुरस्कार जीते हैं। पितौल की भूरी बाई अपनी चित्रकारी के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार हैं। भारत भवन के तत्कालीन निदेशक जे. स्वामीनाथन ने उन्हें कागज पर चित्र बनाने के लिए कहा। भूरी बाई ने अपना सफर एक समकालीन भील कलाकार के रूप में शुरू किया। भूरी बाई अब भोपाल में आदिवासी लोककला अकादमी में एक कलाकार के तौर पर काम करती हैं। उन्हें मध्यप्रदेश सरकार से सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान (1986-87) प्राप्त हो चुका है। 1998 में मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें अहिल्या सम्मान से विभूषित किया।

मेरी पेंटिंग आज देश विदेश में जाती है

पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद भूरी बाई ने कहा कि ये पुरस्कार मुझे आदिवासी भील पेंटिंग करने के लिए मिला है, मैंने मिट्टी से पेंटिंग की शुरुआत की थी। मैं भोपाल के भारत भवन में मजदूरी करती थी और उसके साथ पेंटिंग भी बनाती थी। मेरी पेंटिंग आज देश विदेश में जाती है। मैं बहुत खुश हूं। गौरतलब है कि पिछड़े इलाके से आने वाली भूरी बाई आज भी सही से हिंदी नहीं बोल पाती हैं। लेकिन इस पुरस्कार के मिलने के बाद वह अभिभूत हैं। भूरी बाई अभी जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कलाकार के पद पर पदस्थ हैं।

गरीबी में बीता बचपन| भूरी बाई बरिया का जीवन गरीबी में बीता है। अवॉर्ड की घोषणा होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी चित्रकारी का शौक ही मेरी पहचान बन जाएगी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बाहर जाना तो दूर की बात है, मुझे तो ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती है। मेरा बचपन गरीबी में बीता है, लेकिन अब खुशी है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पाई हूं।

सीडमदर राहीबाई सोमा को पोपरे पद्मश्री सम्मान

दुनिया भर में सीडमदर के नाम से मशहूर महिला किसान राहीबाई सोमा पोपरे को कृषि के प्रति उनके ज्ञान को देखते हुए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राहीबाई एक अनपढ़ महिला है, पर अपनी सफलता की राह में उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी सामने नहीं आने दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी राहीबाई पोपरे को अपने काम के बदौलत बीजमाता की पहचान मिली। राहीबाई पोपेरे स्वयं सहायता समूह के ज़रिए 50 एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर जैविक खेती कर रही हैं, जिसमें वो 17 से भी अधिक फसलें उगा रही हैं। अभी तक 154 देसी बीजों का संरक्षण कर चुकी हैं। उनके पास कुछ ऐसे पुरानी किस्म के चावल और दूसरे अनाज के बीज हैं, जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। राहीबाई ने देशी बीजों को संरक्षित करने के लिए राज्यों की यात्रा की और ऐसे स्वदेशी बीजों के मूल्य के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।

भोपाल स्थित आइसर के वैज्ञानिकों ने किया तैयार, कैंसर जैसे रोगों के इलाज में गिलोय की उपयोगिता का चलेगा पता

पहली बार हुई गिलोय की जीनोम सीक्वेंसिंग खुलेंगे औषधीय पौधे में छिपे गुणों के राज

संवाददाता, भोपाल।

कोरोना महामारी ने गिलोय के फायदे से लोगों को अवगत करा दिया, लेकिन अभी भी हम इसके विशिष्ट गुणों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हैं। इस औषधीय पौधे में छिपे कई गुणों को जानने के लिए विज्ञानी भी लंबे समय से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आइसर) के बायोलाजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर विनीत के शर्मा व उनकी टीम ने चिकित्सकीय गुणों से भरपूर इस पौधे का जीनोम अनुक्रम (सीक्वेंस) तैयार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जीनोम अनुक्रम से अब गिलोय के तत्वों और उनके असर की जानकारी हासिल की जा सकेगी, जो कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। दरअसल, कोरोना वायरस पर गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अपने विशेष गुण के कारण जनमानस में चर्चा का विषय बनी थी। कोरोना के आयुष उपचार में इसका खूब उपयोग भी हुआ। घर-घर में गिलोय बटी और गिलोय शत की पहुंच बन गई, लेकिन गिलोय के अन्य असरकारी गुणों का खुलासा नहीं हुआ। हालांकि इस औषधीय पौधे के रस का आयुष में कई बीमारियों में उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है।

आइसर के विज्ञानी प्रो. विनीत शर्मा के अनुसार दुनिया में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गिलोय के जीनोम पर शोध किया गया है। नौ माह तक लगातार विज्ञानियों की टीम ने इसके जीन जानने और उनका अनुक्रम तैयार करने पर मेहनत की, जिससे गिलोय के जीनोमिक और चिकित्सीय गुणों के बारे में आरंभिक जानकारी हासिल हुई है। एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी आक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गिलोय के असरकारी गुणों के चलते यह अनुक्रम कैंसर और चर्मरोगों में भी इस औषधीय पौधे के असर का पता लगाने में मददगार साबित होगा। डॉ. विनीत ने बताया कि इस अनुक्रम की मदद से इसके गुणों को बेहतर तरीके से पहचानकर वैश्विक स्तर पर कई बड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। यह शोध अमेरिका के प्री-प्रिंट सर्वर में प्रकाशित हो चुका है और आयुर्वेद जगत में इस शोध से एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

यह है जीनोम सीक्वेंसिंग

जीनोम अनुक्रम यानी सीक्वेंसिंग की मदद से हम किसी पौधों में छिपे गुणों का पता लगाते हैं। यह एक प्रकार का कोड होता है, जो चार अक्षर का होता है। यह डीएनए के अंदर एडेनीन (ए), गआनीन (जी), सइटोसीन (सी) और थाइमीन (टी) के रूप में रहता है। ये चारों लेटर क्रम बदल-बदलकर डीएनए में सजे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एजीसीटी, एसीजीटी, एटीजीसी आदि। यह अनुक्रम पौधों में हजारों से लेकर लाखों, करोड़ों तक हो सकते हैं। ये जीनोम अनुक्रम जीन्स बनाते हैं। इसकी मदद से यह भी पता लगाया जाता है कि ये जीन्स कैसे काम करते हैं और इसके बगल में और कौन-कौन से जीन्स हैं। ये आपस में मिलकर किस तरह कारगर हो सकते हैं। विज्ञानी इन्हीं जीन्स का अध्ययन कर किसी भी पौधे के असली गुण पहचानते हैं। जिन गुणों की मदद से बीमारियों का इलाज संभव हो पाता है।

गिलोय में हैं 19 हजार जीन्स

प्रो. शर्मा ने बताया कि सामान्य तौर पर पौधों, प्राणियों और मनुष्यों में 19 से 25 हजार तक जीन्स पाए जाते हैं। गिलोय में भी 19 हजार जीन्स पाए गए हैं। आरंभिक शोध के बाद अब इसके अलग-अलग तत्वों को पहचानकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे स्पष्ट होगा कि इसके जो मैटाबोलाइट्स हैं, वे किस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में कारगर हैं। जीनोम अनुक्रम किसी पौधे की संरचना को जानने की पहली सीढ़ी है। इसे तैयार करने के बाद आगे के शोधकार्यों में आसानी होती है। किसी पौधे में मेटाबोलाइड कैसे बनते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जीन अनुक्रम से समझा जा सकता है। इससे पौधे की और गुणकारी किस्म तैयार करने के साथ ही उसे संरक्षित भी किया जा सकता है।

खुशीलाल आयुर्वेद कालेज में क्लिनिकल ट्रायल में भी यह मिला है कि गिलोय का उपयोग कोरोना में बहुत लाभकारी रहा है। 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए गिलोय का उपयोग ब्रेन टानिक के तौर पर किया जाता है, अन्य मरीजों में उनकी बीमारी के अनुसार मात्रा और दवा लेने का समय डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए।
डॉ. उमेश शुक्ला, प्राचार्य, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, भोपाल

वोकल फॉर लोकलः बुधनी के खिलौनों की मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

संवाददाता, भोपाल।

बुधनी में विगत कई वर्षों से काष्ठ शिल्पकार पीढ़ी दर पीढ़ी लकड़ी के खिलौने बनाते आ रहे हैं। अदभुत काष्ठ कारीगरी, रंग, बनावट और आकर्षक आकार के कारण देश में अलग पहचान है। बुधनी के खिलौनों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को साकार करने के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत बुधनी के खिलौनों का चयन किया गया है।

बुधनी के खिलौनों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बुधनी टॉय फेस्टिवल खिलौनाकारी बुधनी में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इस मेले का वर्चुअल शुभारंभ किया है। टॉय फेस्टिवल खिलौनाकारी के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों को न केवल अपनी शिल्पकला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। खिलौनो के विक्रय के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं ऑनलाइन शापिंग के लिए आवश्यक नेटवर्क/प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। बुधनी के खिलौने बिक्री के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलौना निर्माता कम्पनियों से संपर्क किया जा रहा है।

टॉय फेस्टिवल के माध्यम से खिलौना बनाने वाले क्षेत्रीय एवं आसपास के जिलों से आने वाले कलाकारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम काष्ठ शिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर विचार विमर्श होगा। इससे शिल्पकारों की कल्पनाशीलता एवं नव सृजन का विस्तार होगा। बुधनी टॉय फेस्टिवल के आयोजन से देश-प्रदेश के खिलौना व्यवसायियों का ध्यान आकृष्ट होगा, जो इस पारंपरिक लकड़ी के खिलौनो के व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होगा।

इस टॉय फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य बुधनी को देश में टॉय कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि इस पारंपारिक कला का संरक्षण-संवर्धन के साथ ही कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य यह भी है कि लकड़ी के बने खिलौन होने के कारण बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है। इसी प्रकार बांस, मिट्टी, मोम, लाख, कपड़े आदि सामग्री के उपयोग से खिलौना बनाने को बढ़ावा देना है, ताकि कलाकारों की माली हालत बेहतर करने के साथ ही विलुप्त हो रही कला को संरक्षित भी किया जा सके।

खिलौना निर्माण की वर्तमान स्थिति

बुधनी में पारंपरिक रूप से लकड़ी के खिलौने बनाने वाले 280 शिल्पकार उनके परिवार निवासरत हैं। इन परिवारों में से 120 परिवार वन विभाग के द्वारा पंजीकृत किए गए है। जिन्हें दुधाई की लकड़ी व अन्य आवश्यक लकड़ी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। खिलौना बनाने वाले प्रत्येक परिवार की आय 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह है। वर्तमान में भोपाल नागपुर हाईवे एनएच 69 पर 22 दुकाने खिलौने की हैं। इस प्रकार बुधनी के खिलौनों का लगभग 60 लाख रुपए प्रतिमाह कारोबार हो रहा है।

खिलौना व्यवसाय के विस्तार की कार्य योजना

दस स्व-सहायता समूह का गठन किया जाकर एरिया लेवल फेडरेशन का पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है। शासन के अन्य विभाग, जैसे उद्योग विभाग, इंडो-जर्मन आदि से समन्वय किया जाकर खिलौने क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। बुधनी के खिलौनों को जीआई टैग दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। ई-मार्केटिंग ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर बिक्री के लिए प्रयास किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत का अहम रास्ता है सहकारिताः संघानी

संवाददाता, भोपाल। सहकारी संगठनों की सर्वोच्च संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता सहकारिता से होकर जाता है। इसलिए इस पर फोकस करने की जरूरत है। सहकारी संस्थाओं का रोजगार और जीडीपी में कितना योगदान है इसे जानने के लिए एक सर्वे करवाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद हम इसकी सरकार को जानकारी देंगे, ताकि सभी लोगों को इस सेक्टर की महत्ता का पता चल सके। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों का मुनाफा कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है, जबकि कोई सहकारी समिति फायदे में होती है तो उसका लाभ उसके सभी सदस्यों को मिलता है।संघानी मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली चैप्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। संघानी ने कहा कि सहकारिता में नौकरशाही और राजनीति से जुड़ी कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है। संघानी ने कहा कि देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी सोसायटियां हैं, जिनकी भूमिका ऐसी बनाने की जरूरत है, ताकि उससे आम आदमी को फायदा हो। आईटीओ स्थित आईआईपीए कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय कोऑपरेटिव गवर्नेंस रखा था।

सहकारिता के जरिए मिलेगी नकली कृषि इनपुट से मुक्ति

सहकारिता मंत्रालय के विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. केके त्रिपाठी ने कहा कि सभी पैक्स को कंप्यूटराइज करना और सौ साल आगे की सोच वाली नई सहकारी नीति लाना सरकारी की प्राथमिकता है। इस सिंपोजियम का जो निचोड़ निकलेगा उस पर सरकार विचार करेगी, ताकि आम आदमी को फायदा पहुंच सके। उन्होंने सहकारिता के सात सिद्धांतों की बात की। सहकारिता और नौकरशाही में एक अच्छा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। राज्यसभा सदस्य और जानेमाने किसान नेता बीएस मान ने कहा कि सहकारिता को राजनीति और नौकरशाही के चंगुल से मुक्त करने की जरूरत है।

अच्छी गुणवत्ता और कम समय में आलू की फसल लेने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आलू की टिशू कल्चर लैब शुरू होगी

अब तीन साल में ही तैयार हो जाएगा आलू का प्रजनक बीज

संवाददाता, ग्वालियर। अच्छी गुणवत्ता और कम समय में आलू की फसल लेने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आलू की टिशू कल्चर लैब शुरू होगी। आलू का प्रजनक बीज जो अभी तक चार साल में तैयार होता था वह अब तीन साल में ही तैयार हो जाएगा। समय तो कम होगा ही साथ ही आलू के आकार को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। लैब के लिए आलू अनुसंधान केंद्र की ओर से कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। केंद्र के वैज्ञानिकों का दावा है कि टिशू कल्चर लैब शुरू होने के बाद आलू के प्रजनक बीज को लेकर बेहतर परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश में अभी तक आलू की टिशू कल्चर लैब नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय में टिशू कल्चर लैब तो स्थापित है, लेकिन आलू की टिशू कल्चर लैब नहीं हैं। ग्वालियर में कृषि विवि में भी टिशू कल्चर लैब नहीं है। इस लैब की स्थापना में एक से डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

जनरेशन शून्य से शुरू होगा काम: टिशू कल्चर लैब में जनरेशन शून्य से काम शुरू होगा। इस तरह आलू के टिशू लेकर ट्यूबर विधि से जनरेशन तीन तक काम होगा। अभी टिशू कल्चर लैब न होने की स्थिति में स्टेप एक से स्टेप चार तक काम होता है और चार साल में आलू का प्रजनक बीज तैयार होता है।

बेहटा में भी प्रस्तावित है लैब

ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में भी आलू की टिशू कल्चर लैब प्रस्तावित है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाह ने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि ग्वालियर के बेहटा के पास आलू की टिशू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी। इसको लेकर तैयारी जारी है।

केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में तैयार होगी टिशू कल्चर लैब

कृषि विवि सहित कृषि शोध संस्थानों में आलू को लेकर टिशू कल्चर लैब नहीं है, इसलिए आलू के प्रजनक बीज पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। अब आलू केंद्र में ही टिशूकल्चर लैब स्थापित होने से वैज्ञानिक आलू को लेकर समर्पित ढंग से कार्य कर सकेंगे और परिणाम मिलेंगे।

टिशू कल्चर लैब का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय भेजा है। स्वीकृति मिलते ही लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में अभी आलू की टिशू कल्चर लैब नहीं है। लैब बनने से प्रजनक बीज एक साल कम समय में तैयार किया जा सकेगा, आकार को लेकर भी अच्छा काम हो सकेगा।
डा. एसपी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक व हेड, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र,ग्वालियर

क्रिस्प एवं नर्मदा संस्थान मिलकर निमाड़ क्षेत्र के युवाओं को बनाएंगे आत्मनिर्भर

भोपाल। सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉरमेंस (क्रिस्प) भोपाल एवं निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एण्ड डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन (नर्मदा) खरगौन के मध्य 8 नवंबर 2021 को एक अनुबंध हुआ। यह अनुबंध खरगौन में विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सूर्य कौशल विकास भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान हुआ। इस अवसर पर सुरेश जोशी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली, डॉ. गिरीश बापट, संचालक, ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे एवं कौस्तुभ करमरकर, उपाध्यक्ष, सूर्या फाउंडेशन नई दिल्ली विशेषरूप से उपस्थित थे।

सुरेश जोशी ने अपने उद्बोधन में भारत के आर्थिक विकास के लिए युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया, ताकि प्रधानमंत्री के मूल-मंत्र 'सबका साथ सबका विकास' को पूरा किया जा सके। जोशी ने क्रिस्प एवं नर्मदा संस्थान द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद् के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए कौशल विकास के महत्व पर ज़ोर दिया।

ज्ञान प्रबोधिनी के संचालक डॉ. गिरीश बापट ने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया, ताकि विद्यार्थी स्कूल से ही कौशल का महत्व जानें। क्रिस्प एवं निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एण्ड डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन दोनों ही संस्थान कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यरत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं एवं इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

क्रिस्प के चेयरमेन डॉ. श्रीकान्त पाटिल एवं निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एण्ड डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन की सचिव भारती ठाकुर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। क्रिस्प के चेयरमेन डॉ. श्रीकान्त पाटिल ने क्रिस्प के क्रियाकलापों की जानकारी दी एवं हस्ताक्षरित अनुबंध के उद्देश्य के सम्बन्ध में बताया कि मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाएं शासन के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी सभी संस्थाओं को एकसाथ जोड़कर सुनियोजित ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जायें, जिससे सफलता शीघ्र एवं पूर्णरूप से प्राप्त हो सके।

निमाड़ के युवा बनेंगे आत्मनिर्भर

भारती ठाकुर ने 'निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एण्ड डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन' की गतिविधियों एवं संस्थान द्वारा आदिवासी युवाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे नि:शुल्क रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास एवं अन्य सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती ठाकुर ने बताया भविष्य में दोनों संस्थान, क्रिस्प एवं नर्मदा, साथ मिलकर कौशल विकास के लिए निमाड़ क्षेत्र में ग्रामीण एवं मुख्यत: अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल कार्यक्रम को साझा रूप से संचालित करेंगे एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में निमाड़ क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा में कार्य करेंगे।

सरकार हमेशा आपके साथ, आप अकेले नहीं : कृषि मंत्री

आश्रितों को दिए अनुकम्पा नियुक्ति-पत्र, 41 परिवारों को मिल सहारा

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं सह-अध्यक्ष मण्डी बोर्ड कमल पटेल ने 41 पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। मंत्री पटेल ने अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले आश्रितों और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके दु:ख में सहभागी होकर हमेशा उनके साथ है। वे कभी भी स्वयं को अकेला न समझें। पटेल ने 30 आश्रितों को लिपिक पद पर और 11 को भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के पत्र सौंपे। इस अवसर पर कृषक प्रतिनिधि रामभरोसे पटेल और प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड विकास नरवाल उपस्थित थे। मंत्री पटेल ने अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मन लगाकर कार्य करें। परिवार का संबल बनें। किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। उन्होंने बताया कि आज 41 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति-पत्र सौंपे गये हैं। इसके पूर्व दो चरणों में 53 एवं 36 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति-पत्र सौंपे जा चुके हैं। विगत 5 माह में अब तक कुल 130 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। पटेल ने आश्वस्त किया कि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

मण्डी कर्मचारियों की मांगें की जाएंगी पूरी

कृषि मंत्री पटेल ने मण्डी कर्मचारियों से आव्हान किया कि सभी मन लगाकर प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के साथ निरंतर चर्चा की जाकर एक-एक कर मांगें पूरी की जा रही हैं।

तालाबों में उगने वाली सिंघाड़े की फसल को उन्नत कृषि तकनीक द्वारा मिट्टी के खेतों में उगा कर किसान मुनाफा कमा रहे है

खेत में सिंघाड़े की खेती से ज्यादा मुनाफा और गेहूं के लिए मिल जाती है खाद

ग्वालियर। तालाबों में उगने वाली सिंघाड़े की फसल को उन्नत कृषि तकनीक द्वारा मिट्टी के खेतों में उगा कर किसान मुनाफा कमा रहे है। इनके द्वारा खेतों में पानी भरके सिंघाड़े की खेती की जाती है। पानी होने की वजह से सिंघाड़े की फसल को आवारा मवेशियों द्वारा नुकसान पहुंचाने का खतरा भी बहुत कम होता है। ऐसे में सिंघाड़े की खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे है। शहर से सटे अकबरपुर के किसान अपने खेतों में साल में दो फसल गेंहू और धान ही करते थे। धान में लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने से इन्होंने धान की जगह सिंघाड़े की खेती शुरू की जिसमे काफी अच्छा फायदा हुआ जिसे देख आस पास के किसान भी सिंघाड़े की खेती करने लगे। एक बीघा में तक़रीबन 10 से 15 क्विंटल सिंघाड़ा हो जाता है। जिसमे लगभग तीस हजार रुपये तक का मुनाफा होता है। आज यंहा तकरीबन 100 बीघा में 50 किसानों द्वारा सिंघाड़े की खेती की जा रही है। सिंघाडे की फसल

लेने के बाद खेत में से पानी निकाल कर सिंघाड़े की बेल सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं जो गेहूँ की फसल लेने के लिए कम्पोस्ट का काम करती है। जमीन सूखने पर रोटावेटर चलाकर गेहूँ के लिए जमीन तैयार कर इसमें गेंहू की फसल ली जाती है। इस तरह यंहा के किसान सिघा? और गेंहू की फसल लेकर मुनाफा कमा रहे है। किसान हितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया की सिंघाड़े की खेती ये काफी समय से करते आ रहे है। इनको हर साल अच्छा मुनाफा होता था पर पिछले साल कोरोना के चलते अच्छे दाम नही मिले और इस साल भी भाव उतना नही मिला जितना मिलना चाहिए। फिर भी अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें मुनाफा ज्यादा है। इसीलिए अब यंहा के किसान परंपरागत खेती छोड़ सिंघाड़े की खेती में रुचि लेने लगे हैं। किसान श्यामेन्द्र सिंह का कहना है कि धान की फसल को उगाने में अधिक खर्च आता है। जबकि सिंघाड़ा खेती में एक बीघा में दो हजार की लागत में 10 हजार रुपये तक की आमदनी आसानी से हो जाती है।

दूसरी फसलों में कम मुनाफा होता है। इसे आवारा मवेशी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते इसलिए किसानों का झुकाव सिघड़े की खेती की ओर बढ़ रहा है। किसान बल्लू बाथम बताते हैं कि सिंघाड़ा जून से दिसंबर के मध्य की फसल है। इसकी खेती के लिए खेतो में लगभग एक से दो फीट तक पानी की आवश्यकता होती है। खेतों में भरे पानी में सिंघाड़े की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। हम जून में पौधे की रोपाई करते है और सिंघाड़े की पहली तुड़ाई सिंतबर के महीने में करते हैं। यह आसानी से ओर ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है।

मप्र सरकार ने उठाया जनजातीय वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा

भोपाल। भारत में जनसंख्या के आधार पर मध्यप्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय भाई-बहन निवास करते हैं। प्रदेश का हर पाँचवां व्यक्ति जनजातीय वगज़ का है। लगभग डेढ़ करोड़ आबादी वाले इस वगज़ को समाज की मुख्य-धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने विकास का समग्र एक्शन प्लान बनाकर अनेक योजनाओं को लागू कर उन्हें प्रभावी मूतज़रूप भी दिया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार, स्व-रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास या उनके अधिकारों का संरक्षण, सब दृष्टि से मध्यप्रदेश में व्यापक पैमाने पर कायज़ किए जा रहे हैं। जनजातीय वगज़ को मिलने वाले राशन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनूठी योजना राशन आपके द्वार भी शुरू की जा रही है। योजना का शुभांरभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान से करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि प्रदेश का जनजातीय वर्ग मेहनती और कर्त्तव्यनिष्ठ है। वर्षों से वन क्षेत्रों में रह कर इन्होंने वन और वन्य-प्राणियों का संरक्षण करते हुए अपना जीवन बिताया है। वनों में रह कर जीवन-यापन करने वाले हमारे जनजातीय भाई-बहन अपने अधिकारों की चिन्ता न करते हुए वषोज़ से पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कायज़ कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें उनके अधिकार दिलाएगी। जनजातीय समाज में बिरसा मुंडा जैसे अनेक महानायकों ने भी जन्म लिया और भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे जनजातीय महानायकों से हमारा मध्यप्रदेश गौरव महसूस करता है। महानायक बिरसा मुण्डा की जयंती नरेन्द्र मोदी के आतिथ्य में मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस समारोह पूर्वक मनाने जा रही है।

प्रतियोगी प्रतियोगिताओं के लिए स्मार्ट क्लासेज: प्रदेश में जनजातीय समाज के समग्र विकास की अवधारणा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसले लिए हैं, उसके सुखद परिणामों से जनजातीय वर्ग न केवल आत्म-निर्भर बनेगा, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर विकास की मुख्य-धारा से भी जुड़ सकेगा। जनजातीय समाज में शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से जनजाति के बेटे-बेटियों को 8वीं, 9वीं कक्षा से ही नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लासेज का संचालन भी किया जायेगा। नीट और जेईई में सफल जनजातीय विद्यार्थियों की पूरी फीस भी सरकार भरेगी।

सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार: जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में निर्णय लिया है कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार जनजाति समाज को दिया जायेगा। पायलेट प्रोजेक्ट के अंतगज्त तेंदूपत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति/ग्राम सभा को प्रदान किया जायेगा। वनोपज से बाँस- बल्ली और जलाऊ लकड़ी पर वन समिति का ही अधिकार होगा। समिति उसको बेचकर आय कमा सकेगी। कटाई से जो इमारती लकड़ी प्राप्त होगी, उसका भी एक अंश समिति को जाएगा। देवारण्य योजना में वनोत्पाद और वन औषधि को बढ़ावा देने और इनके अंतर्गत वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। साथ ही

मध्यप्रदेश औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया जायेगा। मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय भाई-बहनों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की एक अहम पहल के अंतर्गत पेसा एक्ट को भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है।

रोजगार और स्व-रोजगार: जनजातीय समाज के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जनजाति के युवाओं को यदि रोजगार के अवसर दिए जाए तो वे अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से समाज का परिदृश्य बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि प्रत्येक जनजाति बहुल गाँव में 4 युवाओं को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। जनजातीय भाई-बहनों को पुलिस एवं सेना में भतीज़ के लिए ट्रेनिंग दिलाई जायेगी। आगामी एक वर्ष में विभिन्न शासकीय विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्व-रोजगार के लिए मछली पालन, मुगीज़ पालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना भी बनाई जाएगी।

सिकल सेल मिशन शुरू रहेगा: जनजातीय वर्ग को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से निजात दिलाने के लिए भी राज्य सरकार ने कमर कस ली है। आगामी 15 नवंबर से मध्यप्रदेश राज्य सिकेल सेल मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। मिशन का शुभांरभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में करेंगे। मिशन में पात्र मरीजों का नि:शुल्क उपचार किया जायेगा। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन के जरिये प्रत्येक जनजातीय ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइप लाईन बिछा कर घर-घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे।

राशन आपके ग्राम: जनजातीय वर्ग के प्रति अति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखण्डों में घर-घर राशन पहुँचाने के लिए राशन आपके ग्राम जैसी अनूठी योजना इजाद की है। इस योजना में हितग्राहियों के गाँव तक वाहन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही स्थानीय जनजातीय युवाओं को राशन वितरण के रोजगार से जोड़ने के लिए, राज्य शासन की गारंटी पर बैंक से वाहन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे प्रत्येक जनजातीय युवा को वाहन से राशन पहुँचाने के लिए प्रति माह 26 हजार रूपये दिये जाएंगे। प्रदेश के ऐसे जिलों, जहाँ जनजातीय महा नायकों की कर्मस्थली रही है, में राज्य सरकार ने बड़े शासकीय संस्थानों का नाम जनजातीय महानायकों के नाम पर रखने की शुरूआत कर दी है। छिन्दवाड़ा विवि का नाम राजा शंकर शाह विवि किया गया है। हम कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश की सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में जनजातीय वर्ग के लिए जो भी किया है और कर रहे हैं वह जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

भारत सरकार की योजनाओं पर अमल में मप्र अग्रणी

भोपाल। मप्र देर से ही सही अपने गठन के समय बूझी गई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले डेढ़ दशक का अरसा इस बात का गवाह रहा है, कि प्रदेश विकास के पथ पर अब आगे ही आगे है। सुविचारित सोच, सुचिंतित नीतियों, फैसलों और प्रेरणादायी नेतृत्व ने सरकार की नीति और नीयत के फर्क को मिटाकर सच्चे अर्थों में प्रदेश के विकास और लोगों की बेहतरी के कामों की तस्वीर में नये रंग भर दिये हैं।

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल अपनी बल्कि भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। मप्र की इन्हीं उपलब्धियों को देखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को भारत की अर्थ-व्यवस्था की ड्रायविंग फोर्स बनने की पूरी क्षमता वाला बताया है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्रके अग्रणी बनने के कुछ उदाहरण हम यहाँ पाठकों से शेयर कर रहे हैं।

स्वामित्व योजना: योजना में आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को भूमि-स्वामी हक प्रदान करने में मध्यप्रदेश अग्रणी है। इसी साल 06 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के 19 जिलों के 3 हजार ग्रामों के 1 लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए। प्रदेश में अब तक 3 हजार 800 से अधिक गाँवों में 2 लाख 71 हजार अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

एनीमिया मुक्त भारत: एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 64.1 स्कोर के साथ मध्यप्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

आयुष्मान भारत योजना: इस योजना के कार्ड जनरेशन में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 57 लाख 44 हजार से अधिक कार्ड बनाये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 25 लाख 36 हजार 917 हितग्राहियों को लगभग 1 हजार 84 रूपए से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

जल जीवन मिशन: एक करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार वाले राज्यों में मिशन की इस साल की भौतिक प्रगति में मध्यप्रदेश का, देश में चौथा स्थान है। मध्यप्रदेश देश का अकेला राज्य है जहाँ सभी जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ एन.ए.बी.एल. प्रमाणित हैं। मिशन के जरिये प्रदेश में 1 करोड़ 22 लाख घरों में से 42 लाख 98 हजार घरों में नल कनेक्शन हो गये हैं।

कृषि अधोसंरचना निधि: इस निधि के उपयोग में मध्यप्रदेश, देश में पहले स्थान पर है। अब तक 805 करोड़ रूपए से अधिक की ऋण राशि प्रदेश में हितग्राहियों को कृषि अधोसंरचा के विकास के लिये प्रदाय जारी कर दी गई है।

नगरीय विकास: भारत सरकार के स्वच्छ सवेज़्क्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के 369 शहर ओडीएफ+ और ओडीएफ++ घोषित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि इन्दौर नगर देश का पहला नगर है जिसे भारत सरकार द्वारा वॉटर प्लस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्दौर को शहरी यातायात में अभिनव वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में मध्यप्रदेश के पाँच शहर क्रमश: इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुए हैं तथा प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन में ही भारत सरकार द्वारा 100 चयनित शहरों की वतज़्मान रैंकिंग में देश के टॉप तीन शहरों में मध्यप्रदेश के दो शहर भोपाल और इन्दौर शामिल किए गए हैं। म्यूनिस्पल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में देश के टॉप तीन शहर में से दो मध्यप्रदेश के शहर इन्दौर और भोपाल हैं। ईज़ ऑफलिविंग इंडेक्स में प्रदेश का एक शहर इन्दौर देश के शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है।

प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना: इस योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को शतप्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण देकर मप्र देश में अव्वल है।

मनरेगा : पिछले वित्त वर्ष में कोरोना काल में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोज़गार दिलाकर मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी रहा है। इस अवधि में मजदूरों के खातों में रिकॉर्ड 6 हजार करोड़ रूपए पहुंचाये गये हैं। इस वित्त वर्ष में अभी तक 79 लाख 62 हजार श्रमिकों को रोज़गार दिया जाकर 3 हजार 924 करोड़ रूपए से अधिक की राशि मजदूरों के खातों में पहुँचाई गई है।

जनजातीय बाचा गांव की महिलाओं ने बनाया ऊर्जा समृद्ध गांव

मध्यप्रदेश को सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में जनजातीय गांवों ने स्व-प्रेरणा से कदम बढ़ाकर गांवों में परिवतज़न लाने की शुरूआत कर दी है। राज्य सरकार की पहल से जनजातीय परिवार अपने हितों के प्रति जागरूक हो गये हैं। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोच को बाचा गांव ने जमीन पर उतार दिया।

जनजातीय बहुल बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील के बाचा गांव के गोंड जनजाति परिवरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे अपनी खुशहाली के लिये नई टेक्नालाजी को अपनाने में पीछे नहीं है। बाचा गांव सौर ऊर्जा समृद्ध गांव के रूप में देश भर में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है।

वर्षों से ऊर्जा की कमी की पीड़ा झेलते-झेलते आखिरकार हम ऊर्जा-सम्पन्न बन गये। हमारा गांव बाचा देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्मनिर्भर गाँव बन गया है। यह बताते हुए अनिल उइके बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वे आदिवासी युवा हैं और बाचा गांव के सौर-ऊर्जा दूत भी हैं। हमारे गांव के सभी 75 घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग हो रहा है। यह बताते हुए खदारा ग्राम पंचायत के पंच शरद सिरसाम कहते हैं कि हमने बाचा को ऊर्जा की जरूरत में पूरी तरह से आत्मनिर्भर गाँव बनाने का संकल्प लिया है। आईआईटी बाम्बे और ओएनजीसी ने मिलकर बाचा को तीन साल पहले ही इस काम के लिये चुना था। इतने कम वक्त में ही हम बदलाव की तस्वीर देख रहे हैं।

धुएं से मुक्ति: बाचा के सभी 75 घरों में अब सौर-ऊर्जा पैनल लग गये हैं। सबके पास सौर-ऊर्जा भंडारण करने वाली बैटरी, सौर-ऊर्जा संचालित रसोई है। इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हुए महिलाओं ने खुद को प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढाल लिया है। पंच शांतिबाई उइके बताती हैं कि सालों से हमारे परिवार मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे थे। आग जलाना, आंखों में जलन, घना धुआं और उससे खांसी होना आम बात थी। अब हम इंडक्शन स्टोव के उपयोग के आदी हो चुके हैं। बड़ी आसानी से इस पर खाना बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री 'राशन आपके द्वार' योजना शुरू

89 आदिवासी क्षेत्रों में सरकार घर-घर देगी राशन, बेरोजगारों को 500 वाहन

संवाददाता, भोपाल।

प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक के पांच सौ बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार 15 नवंबर को वाहन वितरित करेगी। इन वाहनों से आदिवासी अंचलों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को घर-घर राशन वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार 15 नवंबर से मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री 'राशन आपके द्वार' योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंडों में इस योजना का संचालन किया जाना है। योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को घर पहुंचाकर राशन देगी। अब उन्हें राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर नहीं जाना होगा। सामग्री घर-घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार क्षेत्र के आदिवासी हितग्राहियों को ही राशन घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके लिए एक से दो टन परिवहन क्षमता वाले वाहन क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को बैंकों के जरिये दिलाए जा रहे है। 15 नवंबर को ये वाहन इन युवा बेरोजगारों को वितरित किए जाएंगे।

7.40 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक आफ इंडिया देगा कर्ज

वाहनों के लिए बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 7.40 प्रतिशत ब्याज दर पर सात साल के लिए कजज़ बेरोजगारों को उपलब्ध कराया गया है। बैंकों के कर्ज के लिए मार्जिन मनी भी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। एक से दो टन तक की क्षमता के वाहन पर तीन लाख रुपए और एक टन तक क्षमता वाले वाहन पर दो लाख रुपए की एकमुश्त माजिज़न मनी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। हर हितग्राही को केवल 25 हजार रुपए का अंश जमा करना है। शेष राशि कर्ज के रूप में मिलेगी। कर्ज की अदायगी हितग्राही को मिलने वाले मासिक किराए से ली जाएगी। सीएम राशन आपके द्वार योजना में लगने वाले वाहनों पर राज्य सरकार एक टन तक की क्षमता वाले वाहन पर 24 हजार रुपए मासिक किराया देगी जबकि एक टन से दो टन तक की क्षमता वाले वाहन के लिए हर माह 31 हजार रुपए किराया देगी। इसके अलावा नपाई, तुलाई और सामग्री उठाने-रखने का खर्च अलग मिलेगा। एक टन तक क्षमता वाला वाहन साढ़े छह लाख रुपए में और एक से दो टन वाला वाहन 10 लाख 80 हजार रुपए में आएगा। अंत्योदय अन्न योजना में एक रुपए किलो की दर से पैंतीस किलो खाद्यान्न, शक्कर एक किलो प्रति परिवार उपलब्ध कराई जाएगी। यह बीस रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी। वहीं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक रुपए किलो की दर से पांच किलो प्रति सदस्य को खाद्यान्न दिया जाएगा। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को एक रुपए किलो की दर से प्रति परिवार एक किलो नमक भी उपलब्ध कराया जाएगा।

33 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को दी जा रही आर्थिक मजबूतीः वनमंत्री डॉ.शाह

संवाददाता, भोपाल। वनमंत्री विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण के जरिए राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 33 लाख संग्राहकों, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं, को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है। इन वर्गों को तेंदूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक और प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) प्रदान किया जा रहा है। इनमें 44 फीसदी महिलाएं हैं। वनमंत्री डॉ.शाह ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के व्यापार से होने वाली शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में बोनस, 15 फीसदी वन विभाग की देख-रेख में विकास और प्रशिक्षण आदि के लिए और 15 फीसदी ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं और कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में खर्च किया जाता है।

397 करोड़ का हुआ भुगतान- वनमंत्री डॉ. शाह ने बताया कि पिछले वर्ष 15.88 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण में संग्राहकों को 397 करोड़ रूपये मजदूरी का भुगतान किया गया। इस वर्ष 16.60 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित और तेंदूपत्ता के व्यापार से अर्जित हुए शुद्ध लाभ में से 282.47 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की गई है।

प्रति मानक बोरा की बढ़ाई दर

वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निदेज़श पर संग्रहण मजदूरी 2 हजार रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा अनुसार नगद भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। वन धन विकास केन्द्र योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 13 जिलों में 86 केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इसमें एक केन्द्र में 300 संग्राहकों के मान से 25 हजार 800 संग्राहक होंगे। ट्राइफेड द्वारा प्रत्येक केन्द्र में 15 लाख रूपये प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए मंजूर किए गए हैं।

फिजिकल विवि और आईआईटीटीएम के साथ साइन किया एमओयू

संवाददाता, ग्वालियर। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीवी रश्मि ने मंगलवार को ग्वालियर में तीन संस्थानों से एमओयू साइन किया। इसके साथ ही ब्रिटानिया फाउण्डेशन के न्यूट्रीशन वॉलेन्टियरों के साथ चर्चा की। मोतीमहल के मानसभागार में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय, फिजिकल विश्वविद्यालय (एलएनआईपीई) और आईआईटीटीएम (भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान) के साथ एमओयू साइन किया। इसके साथ ही ब्रिटानिया फाउण्डेशन के माध्यम से कुपोषण निवारण के लिये ग्वालियर जिले में किए जा रहे कार्यों के संबंध में वॉलेन्टियरों से विस्तार से चर्चा की। उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि ग्वालियर की तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं से मंगलवार को एमओयू साइन हुआ है। इसके माध्यम से खेल, कृषि और पर्यटन मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष कार्यों को मध्यप्रदेश में तेजी से लागू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ग्वालियर की यह तीनों ही संस्थायें अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि कुपोषण निवारण के क्षेत्र में मप्र सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ग्वालियर जिले में भी ब्रिटानिया फाउण्डेशन के माध्यम से न्यूट्रीशन वॉलेन्टियरों के माध्यम से ऐसे गांवों में कार्य किया जा रहा है, जहां पर कुपोषण है।

कम पानी वाली फसलों के उत्पादन पर किसानों इंसेंटिव देने की तैयारी

धान-गेहूं की फसल न बोने पर इंसेंटिव की तैयारी

संवाददाता, भोपाल।

प्रदेश में धान और गेहूं की फसल के बदले दूसरी कम पानी में उगने वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर राज्य सरकर मंथन कर रही है। इस योजना में ज्यादा पानी वाली फसलों की बजाय कम पानी में पककर तैयार होने वाली फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार इंसेंटिव देने की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में लागू मेरा पानी मेरी विरासत योजना की थीम पर सरकार इस योजना के प्रारूप पर मंथन के बाद इसे लागू कर सकती है।

शिवराज सरकार प्रदेश के उन जिलों के विकासखंडों में खासतौर पर इस योजना को लागू करने पर फोकस कर रही है जहां पानी का संकट गहराने के कारण फसलों और पेयजल पर असर गर्मी में साफ दिखता है। केंद्रीय भूमि जल बोडज़ की रिपोर्ट में एमपी के 24 से अधिक ब्लाक ओवर एक्सप्लायटेड हैं। इसलिए इन विकासखंडों में खासतौर पर धान और गेहूं की फसल के बदले अन्य फसलें उगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है। ऐसी स्थिति में किसानों को परंपरागत धान और गेहूं की फसल न लगाने पर इंसेंटिव देने पर भी विचार किया जाएगा। सीएम सचिवालय ने जल

संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की योजना पर मंथन को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव कृषि, प्रमुख सचिव कृषि और उद्यानिकी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के लिए फैसला किया है।

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली बैठक में फसल विविधीकरण (क्राप डायवर्सिफिकेशन) पर चर्चा होगी। इसमें मोटे अनाज के उत्पादन और उनकी खपत को बढ़ावा देने के साथ दलहन और तिलहन वाली फसलों के उत्पादन पर आने वाले सालों में अपनाई जाने वाली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात, चंदन और अगर के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ चिनोर किस्म के जीआई टैग को बढ़ावा देने पर भी सरकार फोकस करेगी ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि की जा सके।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

कृषक समुदायों को कृषि मंत्री ने दिया पुरस्कार

संवाददाता, भोपाल।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में कृषि की प्रधानता है जो हमारे मन में भी है। इसकी प्रगति के लिए इस क्षेत्र को नए आयामों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए सरकार सारे प्रयत्न कर रही है। अनेक योजनाएं व कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। तोमर ने यह बात पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, कृषक पुरस्कार व कृषक मान्यता पुरस्कार वितरित करते हुए कही। ये पुरस्कार किसानों और किसानों के समुदायों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, जो उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया है और चयन की गई व परिरक्षित सामग्री का पंजीकरण किए जाने योग्य किस्मों में जीन के दाता के रूप में उपयोग किया हो।

कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को आय सहायता दे रही है, वहीं गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, साथ ही किसानों को पर्याप्त अल्पकालिक ऋण मुहैया कराया जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिक समयानुकूल व आवश्यकतानुरूप कुशलता से अनुसंधान कर रहे है एवं फसलों की ऐसी नई किस्में ईजाद की जा रही है, जो जलवायु तथा पर्यावरण के अनुकूल हो। तोमर ने कहा कि परंपरागत पौध किस्में हमारी विरासत है, जिनकी भले ही कम उपलब्धता हो लेकिन इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, इनका संरक्षण व पोषण किया जा रहा है। इस दृष्टि से देश में कानून व प्राधिकरण बनाया गया है। प्राधिकरण के देश में अनेक कार्यालय व बड़े पैमाने पर गतिविधियां हैं, जिसकी पहुंच आम किसानों तक हो रही है। यह प्राधिकरण किसानों के पंजीकरण, मान्यता तथा सम्मान की दृष्टि से भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा सभी लोग प्रकृति व देश के प्रति दायित्व पूरा करें।

2016-17 से वर्ष 2019-20 के पुरस्कार

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के लिए दिए गए। प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और दस लाख रुपए नकद दिए गए। पुरस्कार निम्नलिखित कृषक समुदाय को प्रदान किए गए हैं- कलसुबाई परिसर बियाने संवर्धन सामाजिक संस्था (अकोले, महाराष्ट्र), नट्टू मंचोटिल एजुकेशनल एंड इंडिजिनियस फ्रूट प्लांट्स कंजर्वेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट (कन्नूर, केरल), लाल चावल किसान रोहडू (शिमला, हिमाचल प्रदेश), दंसुरी अग्रिल फार्मिंग को-आपरेटिव सोसाइटी (असम), भूमि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसायटी (कर्नाटक)।

समुदायों को दिया गया प्रशस्ति पत्र

पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20) के लिए प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और डेढ़ लाख रुपये नकद दिए गए। इनमें बंधन उराव (झारखंड), ममताबाई देवराम भांगरे व दतात्रेय नानासाहेब (महाराष्ट्र), दीनदयाल यादव, संजय प्रकाश चौधरी, लिंगूराम ठाकुर व हेत्रम देवांगन (छत्तीसगढ़), एस. बोरेगौड़ा व एमवी प्रकाश राव मंचले, मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी, कटराहल्ली कलप्पा व पूनाचा एन. (कर्नाटक), सत्यनारायण बेलेरी (केरल), वल्लभभाई वासरामभाई मरवानिया (मरणोपरांत) (गुजरात), प्रेम सिंह चौहान (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं।

पादप जीनोम संरक्षक कृषक मान्यता (वर्ष2017-18 से वर्ष 2019-20)

प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और एक लाख रुपये नकद प्रदान किए गए, इनके विजेता हैं एसएस परमेश, श्रीनिवास मूर्ति, शिवगौड़ा एम. पाटिल व केटी वेदमूर्ति (कर्नाटक), आलोक कुमार दास (पश्चिम बंगाल), कल्लुवेलिलवेर्की जॉर्ज व रेजी जोसेफ (केरल) तथा श्री बोलोराम सरोंगसा (असम)। तोमर ने किसानों की किस्मों के संग्रह का विमोचन किया व संरक्षित पौधों को पानी दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे विशेष अतिथि थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र, कृषि एवं बागवानी आयुक्त डॉ. एसके मल्होत्रा, अपर सचिव विवेक अग्रवाल, कृषि वैज्ञानिक आरबी सिंह सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद थे। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. केवी प्रभु ने स्वागत भाषण दिया। प्राधिकरण के सदस्य व कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्विनी कुमार ने आभार माना।

जबलपुर जिले में अब नरवाई जलाना दंडनीय अपराध

प्रवीन नामदेव, जबलपुर,

खेतों की नरवाई जलाने पर जिलेभर में रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण की सुरक्षा व लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने धारा 144 के तहत जिले की सीमा में गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के डंठल, नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने कहा कि नरवाई में आग लगाना कृषि के लिए नुकसानदायक होने के साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं सामने आई। हादसों के कारण कानून व्यवस्था के लिए विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं। उन्होंने कहा कि नरवाई एवं धान का पैरा जलाने पर खेत की आग के अनियंत्रित होने का खतरा रहता है। इससे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होने के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति घटती है जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। जबकि खेत में पड़ा कचरा, भूसा डंठल आदि सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं।

मवेशियों के चारे का संकट : कलेक्टर ने कहा कि गेहूं एवं धान की फसल कटाई में हार्वेस्टर का चलन बढ़ा है। कटाई उपरांत बची नरवाई से भूसा बनाकर मवेशियों के चारे का संकट दूर किया जा सकता है। इसी तरह धान का पैरा भी मवेशियों के चारे के लिए उपयोगी होता है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

प्रधानमंत्री-स्वनिधि योजना में मप्र देश में प्रथम : नगरीय विकास मंत्री

संवाददाता, भोपाल,

प्रधानमंत्री-स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये दिये गये लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों ने इस योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि योजना में निधार्ज़रित लक्ष्य के अनुसार 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को लाभांवित किया जा चुका है। मंत्री सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिये बधाई दी है।

सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने की खुशी जाहिर

सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा शंकर मिश्रा ने टवीट किया है कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश पथ-विक्रेताओं की समृद्धि करने के प्रयास में शुरू से ही अग्रणी रहा है। अब मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने प्रधानमंत्री-स्वनिधि योजना के अंतर्गत 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण वितरित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से पथ-विक्रेताओं का बुरा हाल था। इन्हें पुन: अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 जुलाई 2020 को पीएम-स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। इसमें पथ-विक्रेताओं को ब्याज मुक्त 10 हजार रूपये का ऋण दिया जाता है। योजना में 10 हजार रूपये के ऋण को अदा करने वाले पथ-विक्रेताओं को द्वितीय चरण में 20 हजार और फिर 50 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश देश में अव्वल है।

3 वर्ष में आत्म-निर्भर हो जाएंगी प्रदेश की गौशालाएं: स्वामी अखिलेश्वरानंद

गौग्रास के लिए प्रतिदिन निकालें 10 रुपए

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने आगामी गोपाअष्टमी से गौग्रास के निमित्त रोज 10 रुपये अपनी गुल्लक में जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगली गोपाअष्टमी पर यह राशि 3650 रुपये निकट की गौ-शाला में दान करें। यदि प्रदेश के एक करोड़ नागरिक भी इसमें सहयोग करते हैं, तो प्रतिवर्ष 3650 करोड़ की राशि गौ-शालाओं को मिलेगी। उन्होंने कर्मचारियों और जन-प्रतिनिधियों से भी एक दिन का वेतन साल में एक बार गोपाअष्टमी के दिन गौ-शाला को दान करने का आग्रह किया। इससे गौ-शालाएं 3 वर्ष में आत्म-निर्भर हो जायेंगी। बेसहारा गौवंश की बेहतर देखभाल के साथ इनके कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएँ भी समाप्त होंगी और भारत की गौग्रास की पवित्र परम्परा लुप्त और सुप्त नहीं होगी।

स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य शासन द्वारा 900 करोड़ रुपये से गौ-शालाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में कुल 1728 गौ-शालाएं संचालित हैं, जिसमें 2 लाख 39 हजार बेसहारा गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। एक गाय की देखभाल के लिये 20 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। लेकिन शासन के यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसमें जन-सहयोग और जन-भागीदारी की नितांत आवश्यकता है।

देश में गौवंश घटा पर मध्यप्रदेश में बढ़ोत्तरी

स्वामी अखिलेश्वरानंद ने बताया कि मध्यप्रदेश देश में सवाज़धिक गौवंश और गौ-शालाओं वाला प्रदेश है। देश में गौवंश घटने के बावजूद मध्यप्रदेश में बढ़ोत्तरी हुई है। देश का 20 प्रतिशत गौवंश मध्यप्रदेश में है। देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्यप्रदेश में होने से इसका लाभ भी गौवंश को मिलता है।

गौ-शाला दान राशि आयकर मुक्त

उद्योगपतियों और सम्पन्न लोगों से गौ-शालाओं के लिये बड़ी दान राशि की अपील करते हुए स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि यह राशि आयकर से मुक्त है। बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश में गौ हत्या संज्ञेय अपराध

मप्र गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मप्र में गौ हत्या संज्ञेय अपराध है। यहाँ आरोप सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि गाय राष्ट्र माता ही नहीं, बल्कि गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है।

विकसित होंगे गौवंश वन्य विहार

बोर्ड द्वारा जंगलों के पास गौवंश वन्य विहार विकसित किये जा रहे हैं। गौवंश को जंगल से आहार और वन को गोबर से खाद मिलने की प्रकृति द्वारा की गई एक व्यवस्था है। रीवा जिले के बसावन मामा क्षेत्र में 5 पंचायतों को मिलाकर 51 एकड़ क्षेत्र में गौवंश वन्य विहार विकसित किया गया है, जिसमें 4 हजार गौवंश हैं। जबलपुर जिले के गंगईवीर में 10 हजार गौवंश के लिये वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। दमोह जिले में भी 4 हजार गौवंश की क्षमता वाला वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। आगामी 12 नवम्बर को सागर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की भी स्थापना की जा रही है। आगर-मालवा के सुसनेर में 400 एकड़ में कामधेनु अभयारण्य विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान में 3400 बेसहारा, वृद्ध और बीमार गायों की देखभाल की जा रही है।

देशी गायों का दूध होता है स्वास्थ्यवर्द्धक

स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि मध्यप्रदेश में 4 प्रजाति का देशी गौवंश पाया जाता है, जिनका दूध गिर गाय की तरह ही स्वर्णयुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाला है। देशी गाय के दूध में सभी पोषक तत्व पाये जाते हैं, जबकि विदेशी गाय के दूध में वैज्ञानिकों ने विषैले तत्वों की भी उपस्थिति पाई है। संचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री आर.के. मेहिया भी उपस्थित थे।

योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन

किसानों के लिए मुर्गीपालन फायदे का सौदा, जानें प्रक्रिया

संवाददाता, भोपाल

मुर्गीपालन उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, जो एक सफल कृषि-व्यवसाय में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मुर्गीपालन करके आप अंडे, पंखों का प्रोडक्शन आदि में कमाई कर सकते हैं। यूं तो मुर्गीपालन काफी सफल व्यवसाय है, लेकिन कई बार लोग कम जानकारी की वजह से असफल हो जाते हैं। कई दशकों से चल रहे मुर्गी पालन में कई ऐसे पेच हैं, जिन्हें समझना आपके लिए काफी जरूरी है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप एक सफल मुर्गीपालन कर सकते हैं और अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं।

कम राशि से शुरू कर सकते हैं मुर्गीपालन

मुर्गीपालन का सबसे बड़ा एक फायदा यह भी है कि इसके लिए आपको अन्य बिजनेस की तरह काफी ज्यादा राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। कम राशि की मदद से भी आप मुर्गीपालन की शुरुआत कर सकते हैं। जब तक आप बहुत बड़े स्तर पर मुर्गीपालन की शुरुआत न करना चाहें, तब तक तो आपको बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। आप अपने ही घर या गांव में किसी खाली जगह में मुर्गी पालन कर सकते हैं।

कम समय में ज्यादा रिटर्न!

मुर्गीपालन करके आप कम समय में ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें होने वाले खर्चे ज्यादा नहीं होते हैं. ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा, हाई मैनटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती है। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप की मुर्गियां किसी बीमारी की चपेट में न आएं। इसके अलावा, उन मुर्गियों को सांप, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली आदि से भी बचाकर रखना होगा।

मुर्गियों को किस खाने की जरूरत?

मुर्गीपालन में अच्छी कमाई करने के लिए जरूरी है कि आपकी मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा हो. इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, विटामिन, प्रोटीन आदि की जरूरत होती है। बाजार में मुर्गियों को खिलाने वाले कई तरह के आहार उपलब्ध हैं, जिसे आप खरीदकर उन्हें खिला सकते हैं। वहीं, जब मुगिज्यां चूजे देती हैं तो चूजों को 48 घंटे बाद ही पहली खुराक दी जानी चाहिए। इसके अलावा, पीने के साफपानी की व्यवस्था भी हमेशा रखनी चाहिए।

मुर्गीपालन व्यवसाय में लागत

मुर्गीपालन का मुख्य लाभ यह है कि इसे शुरू करने के लिए ज्यादा राशि की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप 1500 मुर्गी का पालन करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको 50, 000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है।

कितना आएगा मुर्गीपालन में खर्च

किसी भी बिजनेस को शुरू करने में आने वाला खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े स्तर पर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप मुर्गीपालन छोटे पैमाने पर करने की सोच रहे हैं तो इसमें 50 हजार से एक लाख रुपये तक का खर्चा आ सकता है। वहीं, जैसे-जैसे बिजनेस का आकार बढ़ता जाएगा, उसकी लागत में भी इजाफा होगा। मुर्गीपालन के लिए आप विभिन्न बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक से भी पोल्ट्री फार्म के लिए लोन लिया जा सकता है।

सोलर रूफटॉप पर 40 फीसदी, अनुदान पर लगवाएं सोलर पैनल

संवाददाता, भोपाल

केंद्र सरकार नवीकरणीय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें सरकार खासकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार सोलर रूफ टॉप योजना की शुरुआत की है।

देश में सोलर रूफटॉप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफ टॉप सब्सिडी योजना भारत सरकार की एक पहल है। केंद्र सरकार सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। वहीं इस योजना के तहत सरकार उपभोक्ताओं को सोलर रूफ टॉप लगवाने पर सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इसके इस्तेमाल से बिजली की खपत कम होगी। सरकार का उद्देश्य 2022 तक 100 गीगा वॉट सौर ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है। इसमें से 40 गीगा वॉट ऊर्जा छत पर लगे सोलर पैनल से प्राप्त करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

यदि आप 3 किलोवाट तक के सोलर रूफ टॉप पैनल को लगवाते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 40प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करायी जाएगी और अगर आप 10किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सोलर की सब्सिडी आवासीय, सरकारी, सामाजिक और संस्थागत क्षेत्र के लिए उपलब्ध की गयी है।

सोलर पैनेल के फायदे

बता दें कि सोलर को ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्योंकि सोलर पैनल से ऊर्जा पैदा करने में कोई प्रदूषण नहीं होता। सोलर सिस्टम पूरी तरह सूर्य की रोशनी पर आधारित है।

राजस्व मंत्री के नवाचार को मिल रही सराहना

भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े की समय सीमा बढ़ाने के राजस्व मंत्री ने दिए निर्देश

प्रदेश में पहली बार तैयार हो रहा कम्प्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड

ड्रोन सर्वेक्षण एवं योजनाओं की मैदानी हकीकत जानने संभाग स्तर पर समीक्षा करेंगे गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल, संवाददाता

प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा एक नवंबर से प्रारंभ किए गए भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े को आगामी 15 दिन तक बढ़ाने के निर्देश राजस्व मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए। दरअसल, प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए प्रारंभ किए गए राजस्व विभाग के नवाचार भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े में राजस्व से जुड़ी विभिन्न त्रुटियों के सुधार को लेकर जनता में बढ़ती रूचि को ध्यान में रखते हुए राजस्व मंत्री राजपूत ने मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पखवाड़े की अवधि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश अफसरों को दिए। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी, प्रमुख राजस्व आयुक्त संजय गोयल, आयुक्त भू अभिलेख ज्ञानेश्वर पाटिल सहित विभाग के अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक के दौरान श्री राजपूत ने यह भी तय किया कि सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना तथा भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े की जमीनी हकीकत जानने के लिए वह संभागवार योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

राजस्व मंत्री ने तय किया है कि समीक्षा की शुरुआत मालवांचल के इंदौर से की जाएगी। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा अन्य संभागों में इन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा राजस्व मंत्री श्री राजपूत करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से प्रारंभ किए गए भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े में अब तक 33 लाख 6 हजार 664 अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को सुधारा गया। उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के कारण भूमि स्वामियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व मंत्री के निर्देश विभाग द्वारा भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े की शुरुआत की गई। दरअसल, राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रीय शब्दों के उपयोग के कारण नामों में एकरूपता नहीं रहती थी। साथ ही अभिलेख में भूमि स्वामी के प्रचलित नाम और आधार-कार्ड में वास्तविक नाम भिन्नता के कारण नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों में भी क्षेत्रीय कर्मचारियों को परेशानी आती थी। बैंक से ऋण प्राप्त करने, प्रधानमंत्री किसान एवं फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी भूमिधारक लाभ नहीं ले पा रहे थे। जब इस तरह की परेशानियों से जूझ रही जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अवगत कराया तो मुख्यमंत्री के निर्देश एवं राजस्व मंत्री की पहल पर अभिलेख शुद्धिकरण की शुरुआत की गई।

योजनाओं में गति लाने राजस्व अफसरों को दिए निर्देश

विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा, ड्रोन सर्वेक्षण तथा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के कार्यों में गति लाने के लिए राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में

श्री राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए न्यायालय परिसर, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय तथा जिला पंचायत कार्यालय व कलेक्ट्रेट परिसर में डिस्प्ले बोर्ड / फ्लैक्स लगाए जाएं। उन्होंने विभाग की योजनाओं से जुड़ी छोटी-छोटी फिल्में बनाकर सोशल मीडिया के माध्यस से प्रचार करने के निर्देश अफसरों को दिए। बैठक में राजस्व मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई की आजादी के 70 साल बाद पहली बार मध्यप्रदेश में भूमि का कम्प्यूटीराइज्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए की सभी योजनाओं की लगातार मानीटिरिंग के लिए जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी करें ताकि किसी प्रकार की कोताही ना हो। बैठक में श्री राजपूत ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सीहोर और सागर जिले को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए।

मुख्य सड़कों से हटाया जाएगा अतिक्रमण

समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिले की नगरीय क्षेत्रों से गुजरने वाली मुख्य सड़कों में अतिक्रमण हटाए जाने के निदेज़श राजस्व विभाग के अफ़सरों को दिए। उन्होंने कहा कि बेजा अतिक्रमण की वजह से सड़कों की चौड़ाई घटती जा रही है। जिसे रोकने विभाग के अफ़सर सख्त कदम उठाएं। श्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वे कर 50 हजार ग्रामों में संपतिधारकों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी

परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और दुर्घटनाओं को रोकने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस/ पैनिक बटन तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिग टेप लगाने की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल किया जाए। इसके अलावा समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री श्री राजपूत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 नवम्बर को प्रस्तावित भोपाल यात्रा को लेकर भी व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों से चर्चा की।

ग्वालियर-चंबल अंचल में आठ ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण

ग्वालियर। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य तथा नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आज हुए कायज़्क्रम में ग्वालियर-चंबल अंचल में ढाई करोड़ की लागत वाले 8 ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। ये 8 ऑक्सीजन प्लांट्स ग्वालियर जिले के मोहना और हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुरैना जिले के सबलगढ़, भिंड जिले के गोहद, शिवपुरी जिले के करेरा और पोहरी, गुना जिले के चाचौड़ा और अशोकनगर जिले के चंदेरी उप स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए गए हैं।

इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि पहले अंचल में 12 ऑक्सीजन प्लांट्स चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा दो सिटी स्कैन मशीन,10 एम्बुलेंस, मुरैना में ब्लड सेपरेटर मशीन, बड़ी और पोर्टेबल एक्सरे मशीन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड और अन्य मदों से तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के अस्पतालों में 202 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। जिनमें से 171 क्रियाशील भी हो गए हैं। इन प्लांट्स से 187 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। आपने कहा भारत में वैक्सीन के 109 करोड़ से ज्यादा डोज़ लगना एक कीतिज़मान है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति से ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ीं और देशवासी कोरोना के संकट से बच सके और मरीजों को लाभ हुआ। श्री सिंधिया ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए मंत्री श्री तोमर के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम को राज्य के पंचायत मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह, राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर, भिंड की सांसद संध्या रॉय और गुना के सांसद केपी यादव ने भी सम्बोधित किया।

संगठन के पदाधिकारी भी जुड़े थे कार्यक्रम से

उल्लेखनीय है कि ये ऑक्सीजन प्लांट्स एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ,धरड़ा केमिकल्स कम्पनी, और कृषि रसायन कम्पनी के सीएसआर फंड से स्थापित किए गए हैं। जबकि सबलगढ़ में पीएम केयर्स की सहायता से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस कार्यक्रम में धरड़ा केमिकल्स से नीलेश कुलकर्णी, दीपक सिंह, सतीश बेंगोली, जीएस चांदले, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी से मलय कुमार पोद्दार, कृषि रसायन कम्पनी से राजेश अग्रवाल, अतुल चूरीवाल, अंकिता अग्रवाल के अलावा राजनेता, जन प्रतिनिधि,संगठन के पदाधिकारी और विभिन्न स्थानों से क्षेत्रवासी भी इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

आजीविका मिशन खरीदेगा उपज, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा सस्ता पोषण आहार

समूह की महिलाओं से सरकार कराएगी खेती

भोपाल, संवाददाता

आंगनबाड़ी केंद्रों को ठेकेदारों से सस्ता पोषण आहार उपलब्ध कराने में महिला स्व-सहायता समूह फिर सरकार की मदद करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन पोषण आहार तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल (मूंगफली, गुड़, गेहूं सहित अन्य अनाज) स्थानीय स्तर पर समूह की महिलाओं से खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेशभर में सर्वे कराया जाएगा।

सर्वे से यह पता चलेगा कि किस जिले या क्षेत्र में किस फसल की ज्यादा पैदावार है। वहां समूह की महिलाएं फसल उगाएंगी और पोषण आहार संयंत्र चलाने वाले परिसंघ फसल खरीदकर संयंत्रों को देंगे। इसके लिए कांट्रेक्ट खेती (फसल पैदा करने के लिए आर्थिक मदद) भी देने पर विचार चल रहा है। इस प्रयास से समूह की महिलाओं की आमदनी तो बढ़ेगी ही, उन्हें सस्ते में फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मिशन फसल के भंडारण की भी तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में तीन लाख 33 हजार स्व-सहायता समूह हैं। इनसे 35 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हैं। इनमें से सैकड़ों महिलाओं के पास आधा से पांच एकड़ के खेत भी हैं। जिनमें

वे क्षेत्रवार फसल पैदा करती हैं, पर भंडारण की सुविधा न होने के कारण वे फसल को ज्यादा दिन रख नहीं पातीं और तुरंत में औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। वहीं पोषण आहार के लिए बाजार से सामान खरीदना पड़ता है, जो महंगा भी मिलता है और मिलावट की भी पूरी आशंका रहती है। इस स्थिति को देखते हुए आजीविका मिशन स्थानीय स्तर से कच्चा माल खरीदने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसा करने से जहां पोषण आहार के लिए शुद्ध और सस्ता कच्चा माल मिल जाएगा, वहीं समूह की महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें अपनी फसल कम कीमत में नहीं बेचनी पड़ेगी।

चीनी-तेल का भी इंतजाम करेंगे

गेहूं, दाल, गुड़, मूंगफली सहित अन्य खाद्य पदार्थ स्थानीय स्तर से मिलने के बाद आजीविका मिशन चीनी-तेल का इंतजाम भी स्थानीय स्तर पर करने की कोशिश करेगा। वर्तमान में कुछ समूह तेल का उत्पादन कर रहे हैं, पर वह काफी महंगा है। इसलिए अभी नहीं लिया जा सकता है। वहीं चीनी कोई भी समूह तैयार नहीं करता है। इसका इंतजाम बाद में करने की कोशिश होगी।

देवास संयंत्र से होगी शुरूआत

सरकार ने प्रदेश के सातों पोषण आहार संयंत्र समूहों से चलवाने का निर्णय लिया है। समूह देवास संयंत्र इसी माह संभाल लेंगे। इसके बार धार संयंत्र में उत्पादन शुरू करेंगे।

पोषण आहार के लिए कच्चा माल स्थानीय स्तर से ही खरीदने पर विचार चल रहा है। इससे संयंत्रों को शुद्ध सामग्री मिलेगी, तो समूह की महिलाओं को उनकी उपज का सही दाम मिल जाएगा।
एमएल बेलवाल, प्रबंध संचालक, मप्र राज्य आजीविका मिशन

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)